दूसरी शिकायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नही की जा सकी क्योंकि यह शिकायत निर्वाचन आयोग में मतदान के दिन अर्थात् 11 मार्च, 1972 को ही प्राप्त हुई थी।

---

12 *Hrs.*

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED DISCONTENTMENT AMONG HANDLOOM AND POWERLOOM WEAVERS IN UTTAR PRADESH ON ACCOUNT OF HIGH YARN PRICE

SHRI NARSINGH NARAIN PANDEY (Gorakhpur): Sir, I call the attention of the Minister of Foreign Trade to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

> The reported discontentment among handloom and powerloom weavers in Uttar Pradesh on account of high yarn price, non-availability of financial assistance from nationalised banks and non-disposal of accumulated stock.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE): Mr. Speaker, Sir, As a result of the short crop of indigenous cotton amounting to 53 lakh bales only in 1970-71, there was an acute shortage of cotton and abnormal rise in its prices. Consequently, the prices of cotton yarn increased during this period. The annual production of both cloth and yarn in 1970-71 were the lowest in 20 years. As handloom, powerloom and hosiery units found it difficult to obtain supplies of cotton yarn at reasonable prices, a Yarn Pool Scheme was introduced in February, 1971, to alleviate to some extent the shortage of yarn felt by these sectors. The prices at which participating mills were required to sell yarn were the average of the prices of particular counts attained during October, November and December, 1970. The responsibility for distribution of the yarn allocated under the Scheme rested with the State Governments. The scheme has been extended recently to cover the quarter March-May, 1972. Allocations for this quarter will be finalised shortly.

The Textile Commissioner has allotted 1433 bales of hank yarn (for handlooms) and 4650 cases of cone yarn (for powerlooms) to U. P. for the period from October, 1971, to February, 1972, under the Yarn Pool Scheme. This allocation is equivalent to 90% of the State Government's demand for hank yarn and 86% of the demand for cone yarn. The above percentages were the highest for U. P, among all States. U. P. has accordingly been given a special treatment during October-December, 1971. Allocations for March-May, 1972. are still to be made. Discussions with representatives of the Government of U. P. are being arranged, before finalising the allocation for this quarter.

Of late there has been some difficulty in the regular supply of staple fibre yarn to the weaving units and the prices in the market rose considerably. This has been mainly due to the strike, for nearly 2½ months, in the pulp factory of M/s. Gwalior Rayons who are the main suppliers of staple fibre. However, as a result of the efforts made by the Textile Commissioner, the Man-made Fibre Spinners Association, representing the mills in Northern India, have entered into an agreement with the weavers associations to supply 50% of their production at agreed prices. Under this arrangement, the Spinners Association has placed at the disposal of the U.P. State Textile Corporation 3,500 bales per month of staple fibre yarn for distribution to weavers in U.P. The U.P. State Textile Corporation has already arranged to life the yarn allotted to them in the month of February, 1972. The Association has issued instructions to the mills regarding similar supplies during March, 1972. These supplies are in addition to those being made by the mills through the normal trade channels at market prices. The quantity of 3 500 bales has been arrived at on the basis of 50% of the supplies normally made to the weavers in U.P. by the mills. The U.P Government have stated that their requirements are about 11,000 bales per month. The question of assessing their exact requirements and arranging additional supplies is being considered, in consultation with the State Government and the Spinners Association.

As regard sanction of institutional finance for the development of the handloom indus-

try, a scheme under which the Reserve Bank of India grants working capital finance to weavers' co-operatives, through the Co-operative Banks, is already in force. A Committee consisting of the representatives of the Reserve Bank of India, the State Bank of India and the Secretary, All India Handloom Board, has also been formed to examine the matter and report as to how working capital finance could be provided to weavers' cooperatives through State Bank of India, etc. Further action in the matter will be taken after the Committee has submitted its Report.

With the easing of the cotton supply position, the prices of cotton yarn are likely to come down in the next 2 or 3 months. It is hoped that with the Gwalior Rayons coming into full production, the supply of staple fibre yarn would also improve. The difficulties of the handloom and powerloom weavers in obtaining their raw material requirements will, therefore, be shortlived. The situation is, however, being closely watched and an officer of the Textile Commissioner has been specially deputed to establish liaison with the State Government and the Weavers.

6. We have been informed that the U.P. Government have announced the following two major decisions concerning the handloom industry: -

(i) To appoint an Enquiry Commission to look into the problems of the handloom industry; and

(ii) To set up a Handloom Financing and Marketing Corporation.

We are further informed that the hunger-strike of the weavers has ended after the announcement by the U. P. Government. I may assure the House that the Central Government will render all possible assistance to the State Government in resolving the problems of the weavers.

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो बयान दिया है उस बयान से यह बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मुख्य मंत्री ने कहा कि 11,000 लूम्स के लिए सूत दिया जाय और मंत्री महोदय ने अपने बयान में यह स्वयं ही कबूल किया है कि केवल 3,500 लूम्स के लिए आप जो यार्न दे सके है वह भी श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करना चाहता हू कि उन्होंने दो मिलों को ऐलाट किया। एक मिल तो मऊ की राजा राम जयपुरिया जी की मिल है जहां पर कि यू० पी० गवर्नमेंट को उन्होंने वह यार्न जो ऐलाट किया गया उस को भी देना उन्होने इंकार कर दिया और जब देना इंकार कर दिया तो यू० पी० गवर्नमेंट को कोअरसिव मैथड्स अखत्यार करने पड़े। दूसरी मिल जो यार्न के लिए ऐलाट की गयी वह कलकत्ते की कोई मिल ऐलाट की गई थी। आज तक श्रीमन् उन्होंने कोई कम्पलाएंस नही किया। आज सारे सूबे में 35 लाख हैंडलूम वीवर्स भूखो मर रहे हैं। वह इसलिए भूखों मर रहे है कि आज इधर दस सालों से जो यार्न की प्राइस है चाहे वह स्टैपुल यार्न हो और चाहे वह तौलिए और लुंगी बनाने वाला यार्न हो उस की प्राइस बढ़ती चली जा रही है। मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय की सेवा मे कुछ फीगर्स कोट करना चाहता हूं जिन फीगर्स से यह पता चलेगा कि आज मंत्री महोदय ने और उन के डिपार्टमेंट ने उस तरफ कितना अधिक ध्यान दिया है? यह मेरे पास फीगर्स कौटैन टैक्सटाइल इंडस्ट्री की सन् 1951 से लेकर 1971 तक की हैं। सन् 1951 में जो हमारे सूत का भाव था उस से आज का भाव अगर देखा जाय तो दोनों में काफी फर्क है, कोई दूने का फर्क मालूम होता है। इस सिलसिले में कुछ मोटी मोटी फीगर्स हाउस के सामने पढ़ कर सुना देना चाहता हूं।

स्टैपुल यार्न का 40 नम्बर का जो सूत है वह 44 रुपए से बढ़ कर 60 रुपए तक हो गया। 52 रुपए से 75 रुपए और उस से बढ़ कर 100 रुपये तक हो गया और 60 नम्बर का सूत 80 रुपये से बढ़

[श्री नरसिह नारायण पांडेय]

कर 108 रुपए हो गया। इसी तरह 100 नम्बर का सूत 125 रुपए से बढ़ कर 165 रुपए हो गया। 20 नम्बर का सूत 42 रुपए से बढ़ कर 54 रुपए हो गया जबकि 30 नम्बर का सूत 48 रुपए से बढ़ कर 58 रुपए हो गया। कतान रेशम जिससे कि रेशम की साड़िया बनारस में बनती है, मशहूर साड़ियां होती है उन के भाव 170 रुपये से बढ़ कर 240 रुपये तक हो गये। इसी तरह से जो डाइंग की कौस्ट है वह काफी बढ़ गयी है। कैमिकल के भाव 100 रुपये से बढ़ कर 400 रुपए और 400 से बढ़ कर 700 रुपए तक हो गये। 100 परसैंट से ज्यादा इनक्रीज हो गयी। सूत का भाव और हैंडलूम जोकि गरीब लोग इस्तेमाल करते है उस की बाबत मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हू कि आखिर उन के यह भाव इस तरह से क्यो बढ़ते चले जा रहे है? आज मिलों की हालत यह बन रही है कि 664 मिलो मे से 72 मिलें आप की बद पड़ी हुई है। माननीय मंत्री देखेंगे कि 373 स्पिनिंग मिलें और 291 कम्पोजिट मिलें जोकि आज काम कर रही हैं उनमे से 72 मिले आज बद पड़ी हुई हैं तो क्या उन का राष्ट्रीयकरण करने की ओर आप ध्यान देंगे जिससे कि यह समस्याए तय हो सके?

श्रीमान्, आज सब से बडा सवाल यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में 30 लाख जो वीवर्स के खानदान हैं आज उनका खर्चा बहुत अधिक बढ़ रहा है। उधर ऐक्साइज ड्यूटी बढ़ गयी और दूसरी ओर उस का कौस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़ गया है और सब मिला कर आज कोई 45 परसेंट तक का इजाफा उस के कपड़े में हो गया है। करोड़ो रुपये का सारा माल आज उस के घर में बंद पड़ा हुआ है कोई भी आज खरीददार नही है। उस के लिए कोई मार्केट नही है कोई फाइनेंशियल एसिस्टैंट नही है। आपने नैशनालाइज्ड बैंक्स को कहा है कि वे उनको असिस्टेंस दें। मैं जानना चाहता हू कि कितना पैसा आज तक हैंडलूम के वर्कर्ज को लूम्ज के हिसाब से दिया गया है? क्या यह सही नही कि कोआपरेटिव सेक्टर की जितनी मदद की जानी चाहिये थी नही की गई है? क्या यह भी सच नही है कि दो-दो और तीन साल तक उनकी एप्लीकेशज को उन्होंने पैंडिग मे डाला हुआ है और उनको पैसा नही मिल रहा है? यह जो बर्गालग है, यह न हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इतना ही नही। इटावा की जो एक मिल है वह आज भी दो सौ ग्राम कम बडलों मे सूत सप्लाई कर रही है जबकि दूसरी मिलों को, आन्ध्र की मिलों का तथा और मिलो को तीन सौ ग्राम से ज्यादा बडलो मे सूत सप्लाई किया जाता है। मैं जानना चाहता हू कि इस सब को देखते हुए क्या आप कोई ठोस कार्रवाई करेंगे?

क्या आप मार्किटिंग फैडेरेशन जैसी कोई सस्था बनायेंगे जोकि हैंडलूम क्लाथ को रिम्युनरेटिव प्राइस पर खरीद कर उसका एक्सपोर्ट कर सके? इस प्रकार से एक्सपोर्ट की स्थिति पैदा करके क्या आप माल की खपत की व्यवस्था करेंगे ताकि उनकी बेरोजगारी दूर हो सके? साथ ही सूत के भाव गिराने के लिए क्या आप इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करेंगे या कोई दूसरी इस तरह की व्यवस्था करेंगे?

SHRI A. C. GEORGE: The hon. Member has described in detail the pitiable situation of the weavers in U.P. I am not going to dispute his figures, nor am I going to quarrel over some differences this way or that way. The basic truth is that the weavers' plight is not enviable They are having difficulties. The yarn prices had been going up and the price of their production is not going up appreciably in comparison

with that. But I may submit that many of the difficulties raised by the hon. Member are to be solved at the State level.

During the Fourth Plan period, while finalising the allocations, we are not going into details regarding the different projects. It is for the State Government to do that. The Central Government will be giving block grants or aid or loans. It is for the State Government to allocate money out of these block grants for different schemes and priorties according to priorities. Many of the problems raised by the hon. Member can be solved by the State Government by their paying more attention to the actual problems of the weavers.

As I have said, the problem arose because of the poor crop of cotton last year. We had only 53 lakhs bales and naturally, the yarn prices went up. We needed at least 900 million k.g. of yarn production, but our production was only 865 million k.g. So, there was naturally a shortfall of 35 million k.g. This was reflected in the market prices, and the yarn prices went up. We are taking all measures to bring it down, and those are the measures which I have given in my detailed statement. I hope that the hon. Member is convinced that the Government of India are taking all measures within their purview. The hon. Member has pointing out certain figures prevailing in 1951 and subsequently. I have got figures to show that recently, at least, during the past three or four months, reflecting the fall in prices of cotton, the yarn prices are also going down. I may again assure the hon. Member that we are taking all measures that are within the purview of the Government of India.

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया): मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस मे उन्होंने कहा है कि काटन की पैदावार कम हो गई है और साथ ही हडताल की वजह से कठिनाई पैदा हो गई है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। असल बात यह है कि पूंजी वादी मार्किट के अन्दर बडे पूजीपतियों की लूट से बचाने के लिए आपने अभी तक कोई काम नहीं किया है। अभी तक स्थिति यही है कि बिड़ला और जयपुरिया, इन्होंने ही धागा बनाने के काम पर एकाधिकार जमा रखा है और मनमाने ढग से ये धागे की कीमत तय करते हैं। दिसम्बर से मार्च तक इन्होने खूब धागे के काम को बढ़ाया है। इसकी वजह से कठिनाई पैदा हुई। इस कारण से बिहार तथा दूसरी जगहो पर बुनकरो तथा उनके परिवार के लोगो के मरने की परिस्थिति पैदा हुई। तीन समस्याये है, एक पूंजीवादी बाजार की वजह से गडबडी पैदा होनी है, दूसरे नौकरशाही की वजह से होती है और तीसरे आपकी लापरवाही की वजह मे पैदा होती है। मै जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से बातचीत करके क्या आप जो ये समस्याये है, इनको आप हल करने की कोशिश करेगे? क्या आप इस मे हस्तक्षेप करेंगे या कि इनको आप राज्य सरकारों पर ही छोड़ देंगे? अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो किस रूप मे आप उनको सहायता पहुचायेंगे?

ऐसे मिल मालिक जो मनमाने ढंग से दाम धागे के बढ़ा रहे है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आपके पास कोई अधिकार है कानूनी या नही? अगर नही है तो क्या आप इस चीज को बेलगाम छोड़ देंगे ताकि मनमाने ढग से वे काम करते रह सके?

क्या आप इसका राजकीय व्यापार शुरू करेंगे ताकि धागे की सप्लाई की जिम्मेवारी सरकार पर आ जाए और उसके जरिये बुनकरो को निश्चित दामों पर धागे की सप्लाई होती रह सके?

उनके द्वारा तैयार किए गए माल को विदेशो में भेजने के लिए आपने क्या कोशिश की है? जो मार्किट की समस्या है, वह हल हो सके, इसके लिए आपने क्या किया है? क्या आपने ऐसी कोई योजना बनाई है ताकि नए आजाद हुए देशों में और समाज-

[श्री कमल मिश्र मधुकर]

वादी देशों में इस कपड़े का निर्यात बढ़ सके ?

बैंकों से गारंटी दे कर उनको ऋण मिल सकते है। लेकिन नौकरशाही चूंकि अडंगे अटकाती है, इस वास्ते उनको ऋण नहीं मिल पाते हैं। ऐसी चीज न हो और उनको आसानी से ऋण मिल सके, इसके लिए आप कौन-सी कार्रवाई करने जा रहे हैं ?

मैंने ये जो चार प्रश्न किए है, इनके मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ। आप टालने की कोशिश न करें। ऐसी बात न कहें कि राज्य सरकारों के हाथ में यह चीज है और यह हमारा काम नही है।

अध्यक्ष महोदय : वैसे आप एक ही प्रश्न पूछ सकते है ? लेकिन चार को भी आप एक बना कर पूछ सकते हैं। नम्बर जो आप ने दिया है यह न दिया करें। अगर नम्बर देंगे तो फिर एक ही पूछा जा सकेगा।

SHRI A. C. GEORGE : It is not true that the Government of India were indifferent to the problems of the weavers. I explained in my statement that as early as Feb. 1971 when there were signs of yarn prices going up, we introduced a yarn pool scheme and it was through the scheme that we were operating allotments.

The hon. member was suggesting that there is a lot of exploitation going on between the supplier and the consumer. It is precisely to avoid this that we made the allotment to the UP State Textile Corporation. When the allotment is through the Corporation which is a public sector enterprise, naturally we thought that it would be operated better. So there is no question of exploitation taking place in that sector. The allotment is made to the Corporation itself.

As for handloom export, we have been making all possible efforts to boost it. It is quite visible by our recent attainment also. Last year our handloom export was only Rs. 13 crores. This year, though we had targeted for Rs. 15 crores, I am happy to inform the House that our export is going to beyond it and will reach Rs. 15.7 crores.

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश का सब से बड़ा कुटीर उद्योग है। उत्तर प्रदेश में लगभग साढ़े पांच लाख हथकरघे और पच्चीस हजार पावरलूम चल रहे है, जिन में कुल मिला कर चालीस लाख से ऊपर आदमी काम करते है। यह उन के जीवन का प्रश्न है। यह बुनकरो का असंतोष करीब-करीब बाल-बिन्दु बार्यालिग पायंट, तक पहुँच चुका हैं। उदाहरण के लिए 1 मार्च को उत्तर प्रदेश के सभी बुनकर सैंटरों मे मुकम्मल हड़ताल हुई थी। अकेले मऊ मे 35,000 लोगों ने उस दिन जलूस निकाला था। 13 मार्च से 20 मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी बुनकर सैंटरां मे और मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) तथा (इलाहाबाद) में जयपुरिया की काटन मिलो में जबर्दस्त सामूहिक भूख-हड़ताल हुई थी, जिसकी चर्चा मंत्री महोदय ने अपने बयान में भी की है। 22 मार्च को उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने बीस हजार बुनकरों का एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के इतिहास मे ऐसा प्रदर्शन बुनकरों का इसके पहले कभी नही हुआ था। सरकार से कोई संतोषजनक उत्तर अब तक न मिलने पर आज लखनऊ में उन लोगों की उत्तर प्रदेश ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी इस समय बैठी हुई है, जो आगे के स्वशन सत्याग्रह और जेल गोइंग—का फैसला करने जा रही है।

इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए क्या सरकार निम कदमों को उठाने का विचार कर रही है ? अगर कोई मंत्रालय नहीं, तो क्या इस के लिए नैशनल लैवल पर अलग

से एक डायरेक्टोरेट कायम किया जायेगा? आज जो अस्मी फीसदी बोगस कोआपरेटिव सोसायटिया बनी हुई है, जिन पर कुछ नेताओ का एकाधिकार है और जो उन के खाने, कमाने और आराम की जिन्दगी बिताने का आधार बनी हुई है, क्या उन के बारे मे सम्यक जाच की कोई व्यवस्था की जायेगी?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्यारह हजार गाठो की प्रतिमाम के लिए वितरण हेतु माग की है। उत्तर प्रदेश के मत्री, श्री देवकीनदन विभव, ने विधान सभा मे गत 22 मार्च को ढाई घटे के विवाद के दौरान कहा कि इस विषय मे हमारी जिम्मेदारी कम है और केन्द्रीय सरकार की ज्यादा है। मत्री महोदय के बयान मे मालूम होता है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है और केन्द्रीय सरकार की कम है। हम इस झझट मे नही पडना चाहते है। केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार दोनो एक ही पार्टी की है। मै यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने सरकार जो ग्यारह हजार गाठो की माग की है, क्या केन्द्रीय सरकार उन्हे देने जा रही है या नही; अगर हा, तो कब तक, यदि नही तो क्यो?

जो स्टेपल यार्न बनाने की मिले है, चाहे वे ग्वालियर मे हो या हमारे प्रदेश में, क्या सरकार का विचार उन का राष्ट्रीयकरण करने का है, अगर हा तो कब तक?

करोड़ो रुपये का माल बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और बाराबकी में बुनकरो के पास एकत्र पड़ा हुआ है। क्या सरकार उस समस्त स्टाक को खरीद कर अपने माध्यम से देश-विदेश मे खपाने का प्रयास करना चाहती है या नही?

क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैको से बडे पैमाने पर, सस्ती दर पर, आसानी से उन बुनकरो और पावरलूमो को कर्ज देने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है या नही?

सरकार ने जैसे मिलो के मोटे कपड़े पर पैतीस पैसे फी मीटर की एक्साइज ड्यूटी मे छूट दी है, क्या वैसे ही वह हैंडलूम और पावरलूम के कपडे पर भी छूट देने का विचार कर रही है या नही; अगर नही, तो क्या वह मिलो के कपडे पर दी गई छूट को वापिस लेने के लिए तैयार है या नही?

क्या भारत सरकार—मै इस बात पर जोर देना चाहता हू—कुछ कपडे पावरलूम और हैंडलूम के लिए रिजर्व करने जा रही है, जिन को मिले किसी भी अवस्था मे हरगिज न बना सके? इस समय बुर्जुवा-समाज मे यह सिह और मेमने का फ्री काम्पीटीशन हो रहा है, जिसमे हैंडलूम और पावरलूम मर रहे है और मिले सब को खा-चबा रही है। क्या सरकार हैंडलूम और पावरलूम के लिए कुछ कपडे रिजर्व करने का विचार कर रही है या नही?

SHRI A. C GEORGE Sir, the hon. Member has pointed out that a Minister in the U P. Government has passed on the buck to the Central Government. I do not propose to pass the same buck back to the Uttar Pradesh Government Whatever is the Government of India's responsibility, we are prepared to take it. I was only pointing out that with the recent changes in the allocation of finances necessary for different development projects, block grants and loans are given, and it is for the State Government to decide the priorities and allocate the maximum to whichever field it is necessary.

[Shri A. C, George]

There are certain points at which the Government of India is helpless. For example, regarding co-operatives, I do concede that there are some malpractices going on in the co-operatives, but it may be more within the purview of the State Government to prevent these, and we, on the side of the Government of India are prepared to co-operate with it. Beyond that, such malpractices cannot be stopped by the Government of India alone.

Regarding the allotment of 11,000 bales, it is true that the U.P. Government was the opinion that they needed 11,000 bales, but on a study made by the Textile Commissioner, it was found that it can reasonably be met with 7,000 bales. Out of 7,000 bales, more than fifty per cent were earmarked and allotted. It is not that this Ministry alone is doing this; the normal trade channels are also there. Beyond that the allotment to the U.P. State Textile Corporation is made. The hon. Member says about certain reservations being made for the handloom production. Even now we have got certain reservations for handlooms and powerlooms.

SHRI S.M. BANERJEE (Kanpur): I think the hon. Minister is aware that on 22nd March, 1972 nearly 50,000 handloom weavers from all over U.P. held a big demonstration before the Council House in Lucknow. Their demand was supported not only by us but also by MLAs and MPs of the ruling Congress and other parties. It has been stated in the statement:

> "We have been informed that the U. P. Government have announced the following two major decisions concerning the handloom industry: (1) to appoint an Enquiry Commisssion to look into the problems of the handloom industry and (ii) to set up a handloom financing and marketing corporation."

When such things are done, we feel that the Government is trying to solve the problem by appointing a commission. The problem is acute. The weavers of the country, especially in the eastern districts of U.P. where the industry was thriving as a cottage industry are fighting for their existence. Again, in the matter of granting loans, they say:

> "As regrads sanction of institutional finance for the development of the handloom industry, a scheme under which the Reserve Bank of India grants working capital to weavers' co-operatives, through the co-operative banks, is already in force. A committee consisting of the representatives of the Reserve Bank of India, the State Bank of India and the Secretary, All India Handloom Board, has also been formed to examine the matter and report as to how working capital finance could be provided to weavers' co-operatives through State Bank of India, etc. Further action in the matter will be taken after the Committee has submitted its Report."

The main problem is how to get yarn. About a lakh of weavers are there and they are sandwiched in between these committees. Is it a fact that a present fifty per cent of the yarn is being distributed by the U. P. Taxtile Corporation at Rs. 52. I speak subject to correction. Fifty per cent is being sold in the open market and it has been given to big sharks to sell at a price of Rs. 76/-. Why is it so? Why cannot the Government take action to see that the Textile Corporation or the Central level or the State level distributed it at a reasonable price or why cannot the price be fixed in consultation with the handloom weavers' co-operatives? The U. P. Government estimted the requirements to be 11,000 bales but the hon. Minister thinks it to be inflated and he thinks that the Centre's estimate is 7,000 bales. He says that 50 per cent of it had already been given. Is he aware that unless something is done immediately to give relief to the weavers this industry is not going to thrive but is going to die? If this industry dies, the eastern districts of U. P. will be facing a serious unemployment problem, and there is already unemployment problem, in the State. So, what are the immediate steps taken by the Government, and would they like to meet a delegation of the weavers who met the hon. Minister of Finance in Lucknow at the earliest opportunity to discuss this problem and

appoint a committee with their representatives? It is no use appointing a Committee or Commission without consulting their representatives or including their representatives. The Secretary of the Handloom Board is there, but he is not a representative of the weavers. Would I like to know what short-term and long term measures Government propose to take to check the situation, and whether they are going to invite a delegation of the weavers and discuss the entire matter with them before they take final action. In case this is not done, I am afraid they have decided to take action by the 15th April. As their entire existence is threatened, they have decided to do or die, and naturally it they launch a struggle, it would not be in the interests of the State itself. So, to avert unrest among the weavers, to avert their taking drastic action, may I know whether the Government is prepared to meet them and discuss the entire matter with them at the earliest opportunity?

SHRI A. C. GEORGE : This subject was raised because there was a higher level of prices prevailing for the yarns. In this context, the hon. Members may kindly recollect that two days back we had a discussion regarding the cotton prices going down. It is quite natural that the price of cotton going down will have its reflection on the yarn prices also, and is visible from the figures. The prices are going down for yarn also. This whole problem arose, as I explained in the beginning, because last year we had a short crop, and the encouraging signs of the bigger crop this year are quite evident in the prices of yarn going down. Even then, as soon as signs of higher prices were visible last year, we took prompt measures.

A point was raised about the allocation. it was simply because we found that the demand was slightly inflated, we thought of going into the actuals, and it was found that we could have realistic estimates. Even in that case, the maximum allotment was made to the U.P. Textile Corporation. And now, since the yarn price is going down, I do not think that there is an alarming situation prevailing. But I do agree with the Member that the plight of the weavers is a problem which has to be looked into from a larger angle. From the side of the Government of India we are trying to give all possible financial help as well as marketing facilities. As I explained in the beginning, the export of handloom is going up at least by 20 per cent, and we are giving further incentives in all possible ways. As I explained in the beginning, the Committee which is going into the financial aspect of this is expected to submit its report by May, 1972. By that time we will be able to give the necessary financial assistance to the weavers from all possible angles.

SHRI S. M. BANERJEE : He has not answered my question whether it is a fact that the 50 per cent given to the open market is sold at a much higher rate, and whether they would meet a delegation of the weavers to discuss the matter exhaustively, so that trouble may be averted.

SHRI A.C. GEORGE : In such cases, we welcome suggestions from anybody, from all representatives who are concerned with this particular thing.

श्री झारखंडे राय : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर संकट विषय पर आप विवाद रख लें दो घंटे का क्योंकि सरकार की ओर से जो जवाब मिले हैं, वह बिलकुल असंतोषजनक हैं। ..... (व्यवधान) .....

SHRI S. M. BANERJEE : Unless this is immediately attended to, it will affect half of the State.

12.35 *hrs.*

PAPERS LAID ON THE TABLE

REVIEW OF THE WORKING OF THE NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : I beg to lay on the Table a copy each of the following paper. (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 19A of the Companies Act, 1956:

(1) Review by the Government on the working of the National Projects Construction Corporation Limited, New Delhi, for the year 1970-71.